

***श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर):** महोदय, सदन में आवश्यक वस्तुओं को बढ़ते मूल्य-मंहगाई पर उठाई गई चर्चा पर अनेक सदस्यों ने चर्चा की। सभी ने बढ़ती मंहगाई पर चिंता व्यक्त की तथा सरकार को नाकाम असफल होने की बातें कहीं। सरकार मंहगाई पर नियंत्रण कर पाने में असफल रही।

इस प्रचंड जनसंख्या वाले देश में जहां 30 प्रतिशत से ज्यादा अति गरीब बीपीएल परिवार हैं। इतनी ज्यादा संख्या के इन अति गरीब परिवारों की नींद हराम हुई है। मध्यम वर्ग के लोग भी भयभीत हैं, चिंतित हैं। इस बढ़ती मंहगाई हेतु सरकार तुरंत सक्रिय रूप से कड़क कदम उठाये। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर विशेष ध्यान देकर गरीब जनता को अनाज की आपूर्ति हो, इसी पर विशेष ध्यान दे। जमाखोरी, कालाबाजारी न हो, इसलिए सरकार स्वयं सभी राज्य सरकारों को आदेश दे। जगह-जगह विशेष स्काँड बनाए। कालाबाजारी, जमाखोरी, मुनाफाखोरी पर रोक लगाने हेतु EC एक्ट का बड़े पैमाने पर अमल करने हेतु पहल करे।

देश में गरीबी के कारण बीपीएल परिवार ग्रामीण परिवारों में महिलाओं में रक्तअल्पता, बच्चों में कुपोषण की बढ़ती समस्या पर चिंतित थे लेकिन विद्यमान बढ़ती मंहगाई की वजह इस कुपोषण व रक्तअल्पता पर भी चिंता होनी चाहिए।

अनाज के साथ अन्य वस्तुओं पर भी नियंत्रण हेतु सरकार चिंता करे। इन सभी उत्पादित वस्तुओं पर उत्पादन पर लगने वाली लागत पर भी विचार होना चाहिए।

मैं सुझाव दूंगा कि बढ़ती मंहगाई पर नियंत्रण हेतु उत्पादक उत्पादन लागत से कई गुना अधिक मूल्यों में अनेक वस्तुएं बाजार में बिक्री करते हैं। चाहे साबुन, टूथपेस्ट, बिस्किट, चॉकलेट, दवाइयां अन्य खाद्य पदार्थ, इन सभी के उत्पादन पर लगने वाली लागत पर आधारित बिक्री मूल्य होनी चाहिए लेकिन इस हेतु सरकार ने कोई कानून नहीं बनाया है। उत्पादक कारखानों में बनी वस्तुओं पर अपनी मनमानी ढंग से मूल्य तय करते हैं। इस वजह से मंहगाई अनियंत्रित होती जा रही है।

* Speech was laid on the Table.

मैं सुझाव दूंगा कि सभी उत्पादित वस्तुओं पर जिसमें फूड प्रोसेसिंग की गई वस्तुओं के साथ दवाई, सौंदर्य प्रसाधनों, साईकिल, स्कूटर, मोटर इत्यादि उत्पादनों पर भी लागत मूल्य प्रिंटिंग हेतु सख्ती की गई तो मंहगाई पर नियंत्रण लगाया जा सकता है। यह मैं मांग करता हूँ।

ओश्री रमाशंकर राजभर (सलेमपुर): देश में भीषण बाढ़ एवं भीषण सुखाड़ फैल रहा है, और भीषण मंहगाई फैल रही है, क्या सरकार इस बाढ़ सुखा के विपदा में मंहगाई नहीं रोक सकती, डीजल-पेट्रोल का दाम बढ़ना निश्चित दूरदर्शी निर्णय नहीं था। लेकिन इसके आड़ में जमाखोरी द्वारा कृत्रिम मंहगाई लाना कतई देश हित में नहीं है, दो माह पहले तेलों का दाम बढ़ता है जिस अनुपात में दाम बढ़ता है उसी अनुपात में मंहगाई नहीं बढ़ती मंहगाई उसके पाँच गुना बढ़ी लगती है दाल, चना, मूंग, आटा, चावल, सिमेंट, छड़, मौरंग, सब्जी तेल सब आसमान छू रहे हैं कपड़ा, बच्चों के बैग सबका दाम बढ़ा है आप के माध्यम से सरकार ही बताए कि जब तेल का दाम बढ़ाया गया तो कौन सी फसल तैयार हो गई जिसे व्यापारियों ने मंहगे दामों पर खरीदा और अब मंहगे दामों पर बेच रहे हैं तेल का दाम बढ़ते ही स्टॉक कहाँ चला गया सरकार ने यह देखा की सामानों की जमाखोरी कर तेल का बहाना बनाकर मंहगे दामों पर कैसे सामान उपलब्ध होता जा रहा है किसान से क्या दुश्मनी है जब दाल, मूंग, चना, सब्जी, गेहूँ, चावल, उसके घर से था तो मंहगाई नहीं थी ज्योंही उसके घर से गोदामों में गया क्रय मूल्य से चौगुने तीगुने दामों में व्यापारी बेच रहा है, क्या सरकार बढ़े दाम का लाभ किसानों को दिलाएगी, छड़, सिमेंट माल ढुलाई का बहाना बनाकर उद्योगपतियों द्वारा मंहगा किया गया।

महोदय, जमाखोरों, उद्योगपतियों ने कही इस सरकार को चन्दा तो चुनाव का नहीं दिया था जो उनको मनमानी की छुट देकर देश की जनता का कम्मर तोड़ा जा रहा। सरकार ने उद्योगपतियों जमाखोरों से कहा कि बाढ़, सुखाड़ के भीषण विपदा में दाम न बढ़ाए या सरकार ने पूरे देश में दाम बढ़ाने वालों, खाद्य सामानों की जमाखोरी करने वालों के यहां छाप डालकर वास्तविक स्थिति जानी गई है यह सरकार मंहगाई नहीं रोक पा रही है तो भारत निर्माण की बात क्या करती है इस समय मंहगाई नहीं रुकी तो देश की जनता इस सरकार को कभी माफ नहीं करेगी।

महोदय, यह केवल मंहगाई नहीं है यह कम्मर तोड़ मंहगाई है, इसे नहीं रोका गया तो जनता पहले सांसदों की कम्मर तोड़ेगी फिर सरकार की ऐसी कम्मर तोड़ेगी की दवा नहीं मिलेगी सर्व-विदित है केवल एक प्याज का दाम बढ़ने से चार प्रान्तों की राजग सरकार

समाप्त हुई थी, यहाँ तो हर सामान के दाम बढ़े हैं, कल्पना करिए सुखाड़ से अब किसान और दैनिक मजदूरी कर खाने वालों की क्या दशा होगी, क्योंकि जिसके पाकेट में हजार हो वह 100 की दाल 200 में खरीदे कोई असर नहीं पड़ेगा लेकिन जिनके

* Speech was laid on the Table.

पाकेट में सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण में 37 रुपये प्रति व्यक्ति आय वाला दाल, सब्जी, फीस, चावल, आटा, चीनी, तेल कैसे उपयोग करेगा, सुखाड़ ने महंगाई ने जनता को भुखों मरने पर मजबूर कर दिया है देश की सरकार प्रान्तीय सरकारों से वार्ता कर जमाखोरी को अविलम्ब रोके आवश्यक वस्तुओं पर आवश्यकतानुसार सबसिडी जारी करें और ग्राम पंचायत व टोला स्तर पर भोजन देने का इंतजाम करें आवश्यक हो तो जनता को महंगाई से बचाए।

ओश्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): महोदय, आज पूरा देश महंगाई की ज्वाला से जल रहा है सरकारी घोषणाओं में देश में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। विश्वव्यापी मंदी के कारण महंगाई बढ़ रही है, यही सरकारी तर्क है। फीगर और डाटा से देश का हर क्षेत्र हरा-भरा है।

लेकिन सच्चाई यह है कि कृषि का जीडीपी में हिस्सा आजादी के समय आधे से अधिक था जो अब घटकर 5वें हिस्से से भी कम रह गया है। कृषि से जुड़े आधे लोग अभी भी निरक्षर हैं तथा केवल 5 प्रतिशत लोगों ने ही हायर सेकेण्ड्री तक की शिक्षा पूरी की है। कृषि श्रमिकों में निश्चय ही आय और शिक्षा की बहुत कमी है। जहाँ 1951-52 में अनाज-तिलहन की विकास दर 4.19 प्रतिशत थी, वहीं 9वीं एवं 10वीं योजना में यह क्रमशः 1.49 एवं 1.28 हो गया। इसके बाद यूपीए सरकार में 2005 से 2007 तक यह फीगर 3.52 प्रतिशत हो गया। दालें और सब्जियाँ 1.61 प्रतिशत हो गया।

दाल 80 रु. किलो, सब्जी 30 से 40 रु. किलो। मजदूर की मजदूरी का औसत 40 रु. प्रतिदिन। गेहूँ, चावल, सब्जी, दाल एवं चीनी सभी गरीबों के मुँह से बाहर हो रहा है। किसानों को MSP नहीं मिल रहा है। KCC कुछ सम्पन्न और चालाक किसानों को ही मिल रहा है। शेष करोड़ों गरीब एवं निरक्षर किसान इस सुविधा से वंचित हैं। आज देश में करोड़ों लोग आवास सुविधा से वंचित हैं। राज सहायता का लाभ सरकारी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। मिलावट, जमाखोरी एवं मूल्यवृद्धि सरकार के नियंत्रण से बाहर हैं। मिलावट के नमूनों की जांच करने के लिए न देश के राज्यों में पर्याप्त प्रयोगशालाएँ हैं और न मिलावट जांच करने वाले कर्मचारी फिर भी देश तरक्की पर हैं। क्योंकि गरीब बढ़े जमाखोर/मिलावटखोर बढ़ रहे हैं।

वर्तमान महंगाई कृत्रिम (आर्टिफिशियल) महंगाई है। 2002 से 2005 तक पैदावार की विकास दर में दालें एवं सब्जियों की विकास दर 5.95 प्रतिशत थी जो 2006-2007 में घटकर 1.61 प्रतिशत हो गई। यह डाटा एन.एस.ओ. का है इसके बाद डाटा अपडेट नहीं है। सरकार को इसी समय सतर्क हो जाना चाहिए था कि दालें और सब्जियों की विकास दर कम हो रही हैं। इसके लिए पर्याप्त इंतजाम करना चाहिए था, लेकिन सरकार सो गई थी। वर्तमान प्यास में कुंआ खोदने का कोरा दावा किया जा रहा है जो इस देश की जनता को दिभ्रमित करने का प्रयास मात्र है।

*Speech was laid on the Table.

सरकार के तमाम दावों के बावजूद देश के किसानों को फसल का एम.एस.पी. नहीं मिलता। आज बड़ी-बड़ी कम्पनियाँ एयरकंडिशन में अनाज एवं सब्जी, दाल एवं खाद्य पदार्थों की बिक्री कर रही हैं और उनको मुनाफा भी हो रहा है लेकिन आज हमारे देश का किसान एवं गरीब अनाज एवं सब्जी बेचकर अपने परिवार को भरपेट भोजन नहीं करा सकता। यह फासला सरकार के द्वारा समर्थित है। एस.ई.जेड. के लिए हजारों किसानों और मजदूरों की जान गई। बड़े उद्योगपतियों को गरीब किसानों की जमीन पर सरकार द्वारा कब्जा दिला दिया गया लेकिन आज देश के मजदूरों, बेरोजगारों, किसानों और आम जनता की स्थिति एवं बदहाली बढ़ती जा रही है। देश की स्थिति को तो छोड़ें। राजधानी दिल्ली में पीने के पानी में अमोनिया और क्लोराइड की मात्रा 600 मिलीग्राम प्रति लीटर है जबकि केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड 250 मिलीग्राम क्लोराइड की मात्रा मान्य मानता है। लेकिन सरकार देश की जनता के स्वास्थ्य के लिए चिन्तित नहीं है। तमाम असमानताओं के बीच जनता महंगाई से कराह रही है। एनडीए की सरकार की तुलना में यूपीए सरकार में चार-पाँच गुणा महंगाई बढ़ गई है। तमाम बड़ी कम्पनियाँ ने वस्तुओं का वजन, मात्रा एवं क्वालिटी में कमी कर दी और दाम में वृद्धि। यह मैजिक खेल सरकार के सामने है।

आज देश में वही अनाज है, दाल है, पैदावार है, जनसंख्या है, भारत की जनता की भूख एवं कंजम्पशन शक्ति वही है। यकायक सामान कहां गया? सारी खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ गये। क्या देश में बंगलादेश और पाकस्तान से आकर लोग भारत में अनाज का उपयोग कर रहे हैं?

2008-2009 में दालों का घरेलू उत्पादन 14.2 मिलियन मीट्रिक टन अनुमानित था जितना 2006-2007 में था जो 2007-2008 की तुलना में मात्र 0.6 मिलियन मीट्रिक टन कम है। जुलाई, 2008 में कच्चे तेल की कीमत 147 अमरीकी डालर के स्तर पर पहुंचने पर भी कीमतें आज के अनुपात में नहीं बढ़ी क्योंकि चुनाव कराने थे। विकट स्थिति में भी पे-कमीशन लागू करके देश के नौकरी पेशा वालों को लुभाया गया। अब परिणाम कौन भुगत रहा है, सरकार इसका निर्णय स्वयं करे।

आज भारत के श्रम मंत्री एवं भारत के उद्योग मंत्री ने स्वयं प्रश्नों के उत्तर में यह स्वीकार किया है कि देश में श्रमिकों के लिए बना कानून वैसा प्रभावी नहीं है जैसा कि आईपीसी एवं सीआरपीसी के अन्तर्गत बने कानून और देश में पीएसवीएस के माध्यम से हजारों करोड़ के घोटाले हुए हैं। देश में कृषि वैज्ञानिकों की तैनाती पर प्रश्न किया गया, तो मंत्री जी का जवाब है अभी इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। ऐसी स्थिति में आप देश के किसानों एवं मजदूरों की दशा एवं दिशा कैसे तय करेंगे। रिपोर्ट के अनुसार देश में 2004-05 में बाढ़ से नुकसान 3337 करोड़ रु. हुआ आपदा सहायता निधि से 1286 करोड़ रु. मिला। वृहत, मध्यम एवं लघु सिंचाई योजना की स्थिति दयनीय है।

आज हमारे राज्य झारखण्ड की स्थिति बदतर है। सामाजिक समूहों के अन्तर्गत बीपीएल की जनसंख्या का प्रतिशत 2004-2005 के दौरान अखिल भारतीय एससी 36.8, एसटी 47.3, ओबीसी 26.7 के तुलना में यह आंकड़ा क्रमशः 57.9, 54.2 एवं 40.2 प्रतिशत रहा है।

यह देश की तस्वीर है। जब तक सरकार दलगत एवं राजनीतिक भावनाओं से ऊपर उठकर देश की बदहाली से रू-ब-रू न होगी तब तक समस्या का समाधान संभव नहीं है। सरकार को कृषि विकास दर को बढ़ाने, सिंचाई परियोजनाओं को जमीन पर लागू करने, नदियों को जोड़ने, कालाबाजारियों, जमाखोरों पर रोक लगाने और देश के निर्माणी कम्पनियों द्वारा मूल्यवृद्धि करने की मनमर्जी पर नियंत्रण लगाना होगा, तभी हम देश के करोड़ों गरीबों, मेहनतकशों के साथ न्याय कर सकते हैं। इसके लिए एसईजेड छोड़कर बड़े औद्योगिक घरानों को सरकार का साथ देना होगा और जमाखोरी, कालाबाजारी एवं मिलावट नहीं रूकती है, तो सरकार को जनता से अपील करना चाहिए हम लाचार हैं, हम लाचार हैं। हम एक हैं हम एक हैं।

***श्री वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़):** महोदय, सदन में महंगाई पर चर्चा हो रही है आम आदमी को राहत देने की बात 100 दिन में महंगाई कम करने की बैत यू.पी.ए. सरकार द्वारा की गई थी किंतु 15वीं लोक सभा के गठन के बाद से दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमतें दिन रात बढ़ती जा रही हैं चुनाव के पूर्व पेट्रोल, डीजल की कीमतों में कमी की गई किंतु चुनाव बाद कीमतों को फिर बढ़ा दिया गया दाल खाना तो बहुत दूर की बैत हो गई आम आदमी दाल खरीदने का ही साहस नहीं जुटा पा रहा है वहीं दूसरी ओर 2 लाख टन दाल बंदरगाह पर पड़ी है क्यों नहीं सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम का उपयोग कर रही। कीमत वृद्धि पर अंकुश लगाकर जमाखोरों के विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही अब तो जनता चर्चा करने लगी है जब-जब कांग्रेस की सरकार आती है महंगाई बढ़ जाती है यह हमारे ालए बड़ी गंभीर चुनौती है कि देश की 77 प्रतिशत आबादी सिर्फ 20 रु. प्रतिदिन खर्च करने की स्थिति में है सार्वजनिक वितरण प्रणाली को दुरुस्त कर अनाज गेहूँ, चावल, चीनी शक्कर सहित दालों एवं सभी आवश्यक वस्तुओं का विक्रय उचित मूल्य की दुकानों से होना चाहिए।

एन.डी.ए. की सरकार और यू.पी.ए. की सरकार की तुलना करें तो आज सभी चीजों के दाम बढ़ गये हैं महंगाई का सबसे ज्यादा असर गांव गरीब एवं मजदूर पर पड़ा है लोग भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। गरीब की थाली से निवाला छीनने का काम सरकार ने किया है। सिर्फ चर्चा करने से कोई हल नहीं निकलेगा हम वास्तव में महंगाई कम करना चाहते हैं तो सरकार को सभी राजनैतिक दलों से बातचीत कर ठोस कदम उठाना चाहिए तभी बढ़ती हई महंगाई पर अंकुश लगाया जा सकता है तथा देश में निर्मित होने वाली

अराजकता से बचा जा सकता है अन्यथा कुछ समय में स्थिति इस बढ़ती हुई महंगाई से बहुत विस्फोटक हो सकती है क्योंकि इससे हर परिवार एवं पूरा समाज प्रभावित हो रहा है। अतः दृढ़ इच्छा शक्ति से एन.डी.ए. को मूल्य वृद्धि पर रोक लगाने के सकारात्मक कदम उठाने की आवश्यकता है।

* Speech was laid on the Table.

***श्री नारनभाई कछाड़िया (अमरेली):** महोदय, महंगाई के संबंध में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ।

महोदय, मैं यह कहना चाहूँगा कि आज जो चर्चा का विषय है वह उन 80 करोड़ लोगों से जुड़ा हुआ है जो एक दिन में दो वक्त की रोटी मुश्किल से जुटा पाते हैं, और वह महंगाई है, अभी भारत सरकार महंगाई को शून्य से नीचे दिखा रही है मगर क्या उसका असर रोजमर्रा के राशन पर है? जब मुद्रास्फीति 12 प्रतिशत से ज्यादा थी तब तेल का दाम 42 रु. में मिलता था तथा जब दाम 48 रु. में थी। जब कि आज 90 से ज्यादा है। इसी प्रकार से चीनी, किरोसीन, चावल, गैस इत्यादि रोजमर्रा की आवश्यक चीजों की कीमतें दिन प्रतिदिन आसमान छू रही हैं। इसी वृद्धि को सरकार आंकड़े की बाजीगरी से मासूम जनता को भ्रमित कर रही है और मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहूँगा जब एन.डी.ए. की सरकार थी तब अरहर दाल 28 रु. में जब की आज वही दाल 91 रु. में मिल रहा है और उस समय चीनी 12 रु. में था जो आज 28 रु. है और त्योंहार के चलते 40 रु. होने जा रही है और अभी डीजल जो कि किसानों से सीधा जुड़ा हुआ है। इसके दाम भी दिन प्रतिदिन आसमान छूते जा रहे हैं और गैर के दाम में बढ़ोत्तरी से गृहणियों के बजट चरमरा गए हैं, स्कूलों की फीस में वृद्धि से निम्न और मध्यम वर्ग के लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। जिसका असर भारत के भावी विकास से जुड़ा हुआ है।

अभी सरकार अप्रत्यक्ष रूप से महंगाई को बढ़ा रही है जिससे गरीब लोगों का जीने का हक जो संविधान के 21वें अनुच्छेद के तहत उल्लेखित है। उसे भी छीना जा रहा है।

आज किसानों के लिए उर्वरक, बीज, कीटनाशक आदि के दाम आसमान छू रहे हैं, और उसे सस्ते दरों पर कृषि ऋण नहीं मिल पा रहा है। जिससे साहूकारों के चक्कर में पड़े और ऊपर से सूखे की प्राकृतिक मार ने उसे आत्महत्या के लिए विवश कर दिया है। जो दिन प्रतिदिन हमलोग न्यूज में देखते हैं। जिसमें प्रत्यक्ष रूप से सरकार दोषी है और जब एन.डी.ए. की सरकार थी तो उस समय देश से अनाज को निर्यात किया जाता था लेकिन जब आज यू.पी.ए. की सरकार में हर बीज को आयात करना पड़ रहा है और 5 साल में यू.पी.ए. सरकार ने पूरे देश का नक्शा ही बदल दिया है और सबसे देश आजाद हुआ है। तबसे कांग्रेस की सरकार बोल रही है कि गरीबी हटाएंगे गरीबी हटाएंगे लेकिन गरीबी हटाने की जगह गरीबी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। महंगाई देश को लपेटे जा रही है और यहां कांग्रेस सरकार तमाशा देख रही है। तो मैं यहां संसद में बैठे हुए सभी पार्टी के सांसदों से निवेदन करना चाहूँगा कि इसके लिए कोई ठोस कदम उठाया जाए और महंगाई की गति को कम किया जाए।

* Speech was laid on the Table.

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND MINISTER OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI SHARAD PAWAR): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I am thankful to the hon. Members for having raised many important issues on price rise which are badly affecting a sizeable section of our society...(Interruptions)

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): उपाध्यक्ष महोदय, जब आपने ले करवा दिए हैं तो डिस्कशन क्यों होगी?..(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कह रहा हूँ कि जो परम्परा है, हमने उसी के आधार पर किया है, अपनी तरफ से नहीं किया है। उसमें बोलने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए उनकी बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

⌘(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप लोग कृपया करके बैठ जाइए।

⌘(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मंत्री जी को जवाब देने दीजिए।

⌘(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, आप बोलिए।

SHRI SHARAD PAWAR: Sir, prices, particularly prices of essential commodities is one of the most important issues that have affected a sizeable section of our society...(Interruptions) देश के सभी वर्गों को बढ़ती हुई कीमतों की समस्या एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या लग रही है।

* Not recorded.

दो दिन से सदन में इस बारे में बहस हो रही है। जिन सदस्यों ने इस बहस में हिस्सा लेकर जो बातें इस सदन के सामने रखीं, मैं उन सभी इश्यूज को राजनीतिक दल के तौर पर नहीं देखना चाहता। यह एक गंभीर समस्या है। आज देश में ऐसी परिस्थिति पैदा हुई है। सच बताऊं, तो यह परिस्थिति अपने देश तक ही सीमित नहीं है, देश के बाहर भी कुछ हिस्सों में ऐसी परिस्थिति पैदा हुई है, जिसका असर कुछ पैमाने पर हमारे ऊपर भी हो सकता है। दस दिन पहले इस सदन में मुझे बोलने का मौका मिला था। देश में अनिश्चित मानसून ने एक गंभीर परिस्थिति पैदा की है, जिसका असर कई राज्यों में और खास तौर पर किसानों की खेती, कुछ फसलों पर हुआ। मैंने सदन के सामने उस दिन इस स्थिति को रखने का प्रयास किया था। उस दिन मैंने यह भी बताया था कि कई फसलों का क्षेत्र कम होने की स्थिति दिख रही है, जिसका असर कई फसलों की उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन पर भी हो सकता है। इस परिस्थिति का सामना हम सब लोगों को मिलकर करना होगा, क्योंकि जो कमियां आयेंगी, उसकी कीमत इस देश की आम जनता और खासतौर से समाज का जो गरीब वर्ग है, उनको ज्यादा देनी पड़ेगी। उसी पार्चड भूमि के बारे में इस सदन में माननीय सदस्यों ने राइजिंग प्राइसेज का सवाल उठाया था। कल इस पर डिटेल्ड डिस्कशन हुई, मगर उसी समय राज्य सभा में भी इस पर डिस्कशन हो रही थी और मुझे वहां पर जवाब देना था। इसलिए इस सदन में सभी माननीय सदस्यों का विचार मुझे सुनने का मौका नहीं मिला। मगर सदन के रिकार्ड से जिन सदस्यों ने यहां जो कुछ बातें कहीं, उसे पढ़ने का मुझे मौका मिला। इस मामले में भारत सरकार की इस बारे में क्या नीति रहेगी, क्या कदम उठाएंगे, यह मैं सदन और सदन के माध्यम से देशवासियों के सामने रखने का प्रयास करूंगा।

एक बात मैं शुरू में ही सदन और आपके सामने रखना चाहता हूं कि इस देश में आज यूपीए सरकार द्वारा जिस नीति को स्वीकार किया गया है, उसमें देश की कृषि उत्पादकता कैसे बढ़ेगी, किसानों को ठीक तरह से कीमत कैसे मिलेगी और देश की अनाज की समस्या को हल करने में कामयाबी कैसे मिलेगी, उस पर हमारा एक तरफ से ध्यान रहेगा। वैसे कृषि और किसानों की भलाई की बात हम सोचेंगे। साथ-साथ समाज में जो गरीब वर्ग है, उसकी अनाज की समस्या को हल करने के लिए आवश्यकता पड़ी, तो सब्सिडी का रास्ता स्वीकार करके बिलो पावर्टी लाइन पापुलेशन, अन्त्योदय अन्न योजना में शामिल होने वाले वर्ग आदि के हितों की रक्षा करना, ये दोहरा दृष्टिकोण आज इस सरकार का है। हम इस रास्ते से जाना चाहते थे।

हमने पिछले कुछ सालों में देखा, जैसे मैंने शुरू में कहा कि दुनिया में जो कुछ बदलाव आ रहा है, उसका असर यहां भी कुछ न कुछ हो रहा है। कोई नयी फोर्स सामने आ गयी--इनकम ग्रोथ, क्लाइमेट चेंज, हाई एनर्जी प्राइसेज, ग्लोबलाइजेशन, बढ़ता हुआ अर्बनाइजेशन है।

इनका असर फूड कंजम्प्शन, प्रोडक्शन और मार्केट पर होता है, यह हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं। दूसरी एक बड़ी समस्या देश और दुनिया के सामने आई, इंफ्लेशन की। आज हमें कई क्षेत्रों में कामयाबी मिली है, मगर कुछ महीनों पहले हमने यह देखा कि दुनिया में क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ने एक बड़ी समस्या दुनिया के सामने पैदा की जिसका असर दुनिया की अर्थव्यवस्था पर बुरा हुआ और खास कर डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ज्यादा कीमत देने की नौबत आई। उस परिस्थिति का सामना करके, इसमें कामयाब होकर भारत आगे जा सका। आज सभी जगहों पर, अखबारों में, टेलीविजन पर कीमतों के बारे में डिस्कशन हो रहे हैं, इसे मैं गलत नहीं समझता हूं। इनमें से खास तौर पर परिवारों को घर चलाने के लिए जो चीजें लगती हैं, उन पर सभी का ध्यान ज्यादा

रहता है। इससे पहले हमने देश में महंगाई नहीं देखी हो, ऐसी बात नहीं है। इससे पहले भी हमने महंगाई देखी है, सूखा देखा है, बाढ़ देखी है, मगर इस समय कुछ ऐसे आइटम्स हैं, जिनसे आम जनता और समाज के गरीब वर्गों की नींद खराब होने की परिस्थिति पैदा हो गयी है। इसमें पहली बात हमें पल्सेज के बारे में करनी होगी। इस देश में पल्सेज का उत्पादन बढ़ाने के लिए पिछले कई सालों से प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें कुछ कामयाबी भी मिली। मगर जहां एक तरफ उत्पादन बढ़ने का काम शुरू था, वहीं दूसरी तरफ इसकी डिमाण्ड भी बढ़ रही थी। हमारे देश में इसका जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है, पिछले दो-तीन सालों से वह लगभग 14 या 15 मिलियन टन होता है और देश की जो डिमाण्ड है, वह 17 या 18 मिलियन टन के आस-पास है। इस तरह से हम जो उत्पादन करते हैं और जो हमारी आवश्यकता है, उसमें साढ़े तीन या चार मिलियन टन का गैप है, कमी है। इस गैप को भरने के लिए पिछले कई सालों में भारत सरकार, चाहे एनडीए सरकार रही हो या यूपीए सरकार, ने इम्पोर्ट का रास्ता अपनाया है। एक तरफ अपने देश में उत्पादन बढ़ाने का प्रयास और दूसरी तरफ जो कमी है, उसे पूरा करने के लिए इम्पोर्ट का रास्ता स्वीकार किया गया और इम्पोर्ट भी ज्यादा टैक्स या एक्साइज ड्यूटी के बिना ठीक तरह से कैसे होगा, इस पर ध्यान दिया गया। वर्ष 2008-09 का जो हमारा फसल का सीजन था, इसमें एक बात हो गयी, इस दौरान दालों का उत्पादन बहुत कुछ घटा। इनमें से तीन आइटम्स का उत्पादन घटा - तूर, उड़द और मूंग। जैसा लालू जी ने यहां कहा, आम जनता कुछ ज्यादा नहीं चाहती है, रोटी के साथ उनको दाल चाहिए और उन दालों में भी उनका सबसे ज्यादा ध्यान तूर, उड़द और मूंग की दाल पर होता है। इनमें कमी आई और इसका असर गरीब आदमी पर तथा समाज के अन्य वर्गों पर भी पड़ा। इन तीन आइटम्स का पिछले साल हमारे देश में उत्पादन कम हो गया, जबकि बाकी का इतना कम नहीं हुआ।

श्री शरद यादव (मधेपुरा): आप जो कह रहे हैं, उससे मैं सहमत हूं, लेकिन जैसा बहुत से साथियों ने कहा कि बंदरगाहों पर दालें पड़ी सड़ रही हैं, उस बारे में क्या कहेंगे?

श्री शरद पवार: मैं उस पर भी आऊंगा। हमारे पास आयात करने का ही रास्ता था। वर्ष 2008-2009 में पूरी दुनिया में जो दालों की स्थिति है, सरप्लस दालों का उत्पादन या स्टॉक चंद देशों में ही होता है। जैसे म्यांमार है, अर्जेंटीना है, अमेरिका का कुछ हिस्सा है, आस्ट्रेलिया का कुछ हिस्सा है। इन चार-पांच मुल्कों से दालों का आयात होता है और समस्या को हल करने में मदद मिलती है। इस साल दुनिया में दालों का सरप्लस स्टॉक पांच मिलियन टन था। उसमें से हमने ढाई मिलियन टन खरीदने का काम अंडरटेकिंग्स फर्म्स या भारत सरकार की जो तीन-चार पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, पीईसी, एमएमटीसी, नैफेड, एसटीसी ने दालों का आयात किया। इन्होंने करीब दस लाख टन के आसपास दालों की खरीद की। भारत सरकार की सलाह से पब्लिक सेक्टर की इन यूनिट्स ने दाल खरीदी, वे सरकार के अकाउंट पर नहीं लाए। वे सरकार की सलाह से लाए थे और मार्केट में दालें अवेलेबल कराने की कोशिश उनकी तरफ से हुई। हमारे देश की जो टोटल रिक्वायरमेंट है दालों की और जितना उत्पादन होता है, उसमें गैप हो गया। इसलिए तूर, उड़द और मूंग, इन तीन दालों पर बुरा असर पड़ा और ये दालें आम जनता को अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग कीमतों पर मिलने की परिस्थिति पैदा हो गई। यहां पर तूर की दाल 90 रुपए या 100 रुपए प्रति किलोग्राम तक खरीदने की बात भी उठाई गई। मैं दिल्ली में, कंज्यूमर्स अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से हम जो प्राइस कलेक्ट करते हैं, कल मैं देख रहा था, यहां पर रिटेल के बारे में जो जानकारी आती है, वह देखी थी तो मालूम हुआ कि दालें 75 रुपए से 90 रुपए प्रति किलोग्राम तक अलग-अलग राज्यों में और अलग-अलग शहरों में बिक रही हैं। यह जबर्दस्त कीमत है। आम जनता के लिए सहन करने वाली नहीं है। इस पर कुछ न कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है। क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इसके हमने दो रास्ते स्वीकार किए। पहला रास्ता यह स्वीकार किया कि इसका हल निकालने के लिए एक दीर्घकालीन नीति बनाई जाए। इस साल देश में कई जगह सूखे की स्थिति है, लेकिन दालों का क्षेत्र कैसे बढ़ाया जाए, इस पर ध्यान दिया गया है। मुझे सदन में बताते हुए खुशी हो रही है कि दालों के उत्पादन के सम्बन्ध में जितना क्षेत्र हमने पिछले चार सालों में सोइंग में बढ़ाया है, उतना पहले कभी नहीं बढ़ा। मैं प्रार्थना करता हूं कि अगले 10-15 दिनों में, जहां दालों का उत्पादन होता है, वहां बारिश हो जाए तो परिस्थिति में बदलाव आ सकता है, जल्दी आ सकता है।

दालें पूरे देश में कई हिस्सों में पैदा होती हैं। दालों की ज्यादातर पैदावार कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा, महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा और पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार के भी कुछ हिस्सों में भी कुछ न कुछ उत्पादन दालों का होता है।

मगर सरप्लस प्रोडक्शन देश के अन्य राज्यों में भेज सकते हैं, वह चार राज्यों में ज्यादा होता है, मगर वह बारिश पर निर्भर होता है। कम से कम कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में पानी की स्थिति बिहार और यूपी के मुकाबले ठीक है, अगर यह परिस्थिति अगले तीन-चार हफ्ते ठीक रही तो इसमें सुधार हो जाएगा तो परिस्थिति में बदलाव आ सकता है।

दूसरी तरफ जैसा मैंने कहा कि इम्पोर्ट का रास्ता हमारे सामने है और उस रास्ते पर हम जा रहे हैं। जो सवाल यहां उठाया गया और मेरा ध्यान टेलीविजन की रिपोर्ट और कुछ न्यूजपेपर्स की रिपोर्ट्स पर गया था कि आयात किया हुआ हजारों-लाखों टन माल बंदरगाहों पर सड़ रहा है और वह सरकार का माल है। सदन के माध्यम से एक बात मैं देशवासियों के सामने रखना चाहता हूं कि सरकार ने पल्सेज कहीं से भी नहीं खरीदी हैं। भारत सरकार ने चार संगठनों को सलाह दी कि आप ये इम्पोर्ट कर सकते हैं और जब आप यहां मार्केट में बेचेंगे, उसमें जो घाटा होगा, उस घाटे का कुछ हिस्सा भारत सरकार उठाने के लिए तैयार है। भारत सरकार ने अवेलेबिलिटी की जिम्मेदारी उन्हें दी थी। इन चार संगठनों ने कुछ माल इम्पोर्ट करने का काम किया। पीईसी, एमएमटीसी, नैफेड और एसटीसी, इन चारों संगठनों ने the total contracted quantity is 10,29,140 tonnes. एराइवल की डेट है 22 जुलाई 2009 की। The actual arrival is 9,13,820 tonnes As I said earlier, we have contracted for a quantity of 10,29,140 tonnes. Out of that, 9,13,820 tonnes reached India. यह नौ लाख माल जो पहुंचा है, इसमें से a quantity of 7,03,445 tonnes has been disposed of. That has been disposed of in the open market. कुछ राज्यों ने जो डिमांड दी थी, उन राज्यों की वह डिमांड पूरी की गयी। जो स्टॉक हमारे

हाथ में था वह दो लाख दस हजार टन था और इसमें से जिसका जिक्र माननीय शरद यादव जी ने किया, वह जब हमने जांच की तो सभी पब्लिक सेक्टर यूनिट ने हमें लिखित में बताया है कि जो माल उन्होंने खरीदा, उसमें से कोई भी माल सड़ा नहीं, खराब परिस्थिति में नहीं है। एक बात साफ है कि नैफेड 6 हजार टन माल बाहर से लाया था, वह कोलकाता पोर्ट पर हैल्थ ग्राउंड के क्लीयरेंस देने की आवश्यकता में समय लगा और उसे कस्टम ने क्लीयर नहीं किया था। आज सभी कागजात जो देने की आवश्यकता थी, वे नैफेड ने पूरे किये और सभी माल कस्टम ने क्लीयर किया और जहां भेजना था उसे भेजने में नैफेड कामयाब रहा। इससे एक बात साफ होती है कि आयातित माल सड़ा रहा है, सरकार का आयातित माल किसी बंदरगाह पर पड़ा है, यह रिपोर्ट गलत है। जहां तक इन चार पब्लिक सेक्टर ने लिखित रूप में हमें बतलाया और स्थिति हमने देखी, उससे यह बात जाहिर होती है, साफ होती है कि यह रिपोर्ट सच नहीं है। दूसरी एक बात हो सकती है कि जिस तरह से 10 लाख टन माल ये चार संगठन लाए, उसी तरह से 15-20 लाख टन माल प्राइवेट व्यापारी भी इस देश में लाए। उनका स्टेटमेंट भी मैंने पढ़ा। उनकी एसोसिएशन के माध्यम से एक स्टेटमेंट निकला है "Pulses Importers Association of India." What have they said?

"Several allegations have been doing the round in newspapers that the stocks of pulses are lying in the ports on account of Government or private trade and that, over the months, the quality of the stock has been deteriorating. The Pulses Importers Association wishes to clarify that this is untrue and wish to inform you that the stock position of yellow peas and others at the ports and port cities is as follows and they are in good condition."

प्राइवेट सेक्टर ने भी यह बात साफ तौर से कही है कि जो भी माल आया है, उसमें कोई खराबी नहीं हुई है। इतने बड़े देश में कहीं न कहीं चार बोरी या छह बोरी अगर खराब हो गई और उसका फोटो अखबार या टेलीविजन में आ गया। देश के सामने इतना बड़ा संकट है, तो देशवासियों के मन में भी यह शंका पैदा हो सकती है।...(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद (सारण): मुद्रा पोर्ट में माल पड़ा है।

श्री शरद पवार : मुद्रा पोर्ट में माल नहीं आया है। कोलकाता, मुम्बई, तुतिकोरिन, चैन्नई, विजाग, काकीनाड़ा पोर्ट्स आदि से माल आया है। इसकी रिपोर्ट फूड विभाग ने दी है। दूसरी जगहों से माल नहीं आया है, इस तरह की उनकी रिपोर्ट है।

श्री लालू प्रसाद : गुजरात में अदानी पोर्ट सबसे बड़ा है। वहां सारा माल पड़ा है, लेकिन कोई उठाने वाला नहीं है। आप इसकी जांच करवा लीजिए कि सामान वहां था या नहीं।

श्री शरद पवार : शिपिंग मिनिस्ट्री के अंतर्गत हमारे सभी पोर्ट्स आते हैं। शिपिंग मिनिस्ट्री की तरफ से हर पोर्ट में पलिसिस और चीनी कितनी आई, कब आई, स्थिति क्या है, इसकी लिखित रिपोर्ट हमने मांगी। उन्होंने कहा कि कोलकाता, मुम्बई, तुतिकोरिन, विजाग और काकीनाड़ा पोर्ट्स पर पलिसिस आया है और इनका पूरा हिसाब-किताब उन्होंने भी दे दिया है, चारों प्राइवेट सैक्टरों ने भी दे दिया है तथा प्राइवेट एसोसिएशन, पलिसिस इम्पोर्ट एसोसिएशन आफ इंडिया ने भी दिया है। इनके माध्यम से यह बात सामने आई है कि ऐसी कोई स्थिति पैदा नहीं हुई है। जैसा मैंने पहले कहा है कि इतने बड़े देश में अगर कहीं चार बोरी या पांच बोरी खराब हुई होगी और इसका फोटो अखबार या टीवी के माध्यम से देशवासियों के सामने आया है, तो आप या मैं, कोई भी हो, चिंता होना स्वाभाविक है कि यह ठीक नहीं हो रहा है। यह समझते हुए ही यह मुद्दा यहां उठाया गया होगा। ऐसी स्थिति पैदा न हो, इस बारे में जो ध्यान देने की आवश्यकता है, वह ध्यान हमारी तरफ से दिया जाएगा, क्योंकि पलिसिस हमारे देश में ला कर डिमांड और सप्लाई का गैप पूरा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश करने की आवश्यकता है। इस बारे में हम सहमत हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है।

श्री मुलायम सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, महंगाई पर बहुत बहस हुई है और बहुत तैयारी के साथ कृषि मंत्री जी जवाब भी दे रहे हैं, इसके लिए हम इन्हें धन्यवाद देते हैं, लेकिन क्या मंत्री जी दो बातें मानने के लिए तैयार हैं? लागत खर्च से डेढ़ गुना से ज्यादा कारखाने की चीज नहीं बेची जाए। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जो साधारण सुई है टीबी की, वह लगभग दस रुपए का एक इंजेक्शन आता है। आप उसकी लागत का पता लगाएं तो वह तीन रुपए से ज्यादा नहीं है। वह सुई साढ़े चार रुपए में मिलनी चाहिए। दूसरी बात, एक फसल से दूसरी फसल तक बीस फीसदी से अधिक महंगी पैदावार नहीं होनी चाहिए, जिसे दाम बांधो नीति कहते हैं। दाम बांधो नीति वही सरकार चला सकती है, जिसमें साहस हो और हम उसमें सहयोग करेंगे। क्या मंत्री जी दाम बांधो नीति लागू करेंगे।

श्री शरद पवार : आपने दाम के बारे में क्या कहा है?

श्री मुलायम सिंह यादव : मेरा सवाल दाम बांधो नीति के बारे में है। हमारा कहना है कि कारखाने में बनी चीज बनाने में जो लागत आती है, उसका ड्योढ़े से ज्यादा मुनाफा नहीं कमाना चाहिए।

जैसे एक टी.वी. की सुई है जिसकी लागत कारखाने में लगभग 3 रुपये आती है और बाजार में 10 रुपये बेची जा रही है और स्टोर में वही सुई 225 रु. में बेची जा रही है जबकि कारखाने की बनी हुई चीज जो होती है, उसका खर्चा, उसकी लागत में ड्योढ़े से ज्यादा मुनाफा नहीं कमाना चाहिए और किसान का जो उत्पादन है, वह एक फसल से दूसरी फसल तक 20 फीसदी से लेकर 25 फीसदी से ज्यादा महंगा नहीं होना चाहिए। क्या सरकार दाम बांधो नीति लागू करेगी ?

SHRI SHARAD PAWAR: I come to Minimum Support Price. That is one of the important issues which I also feel it. जो कुछ असर हुआ है, इसका असर डाइरेक्टली और इंडाइरेक्टली हो सकता है, हम जिसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। मगर मैं पहले जिस खास आइटम के बारे में लोगों में नाराजगी है, जिसकी बहुत ज्यादा कीमत आम परिवारों को देनी पड़ती है, इनमें पल्सेज आती हैं, इसीलिए मैंने पल्सेज के ऊपर शुरू में ध्यान दे दिया।

दूसरा महत्वपूर्ण आइटम चीनी है। जहां तक चीनी की बात है, चूंकि चीनी का इस देश में कई सालों से मैं देख रहा हूं कि उसका एक साइकल होता है। 5 सालों का वह साइकल होता है। 5 साल में से 3 साल हमेशा चीनी का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है और 2 साल चीनी का उत्पादन बहुत कम होता है। जब चीनी का उत्पादन बहुत कम होता है, उस समय गन्ने की कीमत बहुत ऊपर जाती है। किसान फिर गन्ना ज्यादा लगाता है और 2 साल के बाद जरूरत से ज्यादा इस देश में पैदावारी होती है। चीनी की कीमत नीचे जाती है, किसान को ठीक तरह से कीमत नहीं मिलती और फिर किसान दूसरी फसल पर शिफ्ट होता है। ऐसी परिस्थिति कई सालों से इस देश में बन रही है। यह चीनी के क्षेत्र में साइकल है। सदन के सदस्यों को याद होगा, 3 साल पहले इस देश में चीनी का उत्पादन कभी भी इतना ज्यादा नहीं हुआ था कि 260 से 300 लाख टन तक चीनी का उत्पादन हो गया, जगह-जगह चीनी के स्टॉक पड़े रहे। चीनी मिल जिनकी जिम्मेदारी किसानों की गन्ने की कीमत देने की थी, वह देने की परिस्थिति में नहीं रही और इसका सबसे ज्यादा बुरा असर उत्तर प्रदेश पर हो गया। मुझे याद है, मुलायम सिंह यादव जी मुख्य मंत्री थे, उस समय वहां के किसानों को ठीक तरह से गन्ने की कीमत मिलनी चाहिए, इस बात पर ध्यान दिया गया। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से चीनी मिल वालों को बुलवाकर जगह-जगह पर जहां कीमत नहीं दी गई थी, वहां कीमत देने की एक परिस्थिति पैदा हो गई। तब किसानों को गन्ने की कीमत मिली। मगर इसके बाद के 2 साल ऐसे हुए कि उत्तर प्रदेश के किसानों को गन्ने की कीमत ठीक तरह से नहीं मिल रही थी और यह बात केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं थी, देश के अन्य राज्यों की परिस्थिति भी ऐसी थी क्योंकि चीनी की कीमत 1000 रुपये टन से नीचे आई थी जिसका उत्पादन, खर्चा इससे ज्यादा है। कारखाने संकट में आ गये, मिल संकट में आ गई। माल बहुत पड़ा था लेकिन इसकी डिमांड नहीं थी, इंटरनेशनल मार्केट में भी डिमांड नहीं थी। इसलिए क्या करना है, यह जरूरत सरकार के सामने आ गई थी। ऐसी परिस्थिति में सरकार ने बफर स्टॉक को फाइनेंशियल सपोर्ट करने का एक कदम उठाया और 800 करोड़ रुपये की राशि इस परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए उन्होंने दी। साथ-साथ एक्सपोर्ट करने के लिए भी मदद की और इससे देश में जो सरप्लस चीनी का स्टॉक था, वह कम करने के लिए कोशिश की गई। मगर जब इतनी कीमत कम हो गई और मुझे याद है कि जब सदन में 3 साल पहले यह बात मैंने कही थी, तब चीनी की कीमत 12, 13 रुपये के आसपास आने के बाद इस सदन में मांग की गई कि चीनी की कीमत और कम होनी चाहिए, तब मैंने सदन में कहा था कि चीनी की कीमत 20 या 22 रुपये तक जब तक नहीं पहुंचेगी, तब तक किसानों को ठीक कीमत नहीं मिलेगी और जब तक किसानों को ठीक कीमत नहीं मिलेगी तो मुझे लग रहा है कि 2 साल के बाद इस देशवासियों को चीनी 27, 28 या 30 रुपये में खरीदनी पड़ेगी क्योंकि किसान दूसरी फसलों पर जाएगा।

मैंने यह बात सदन में कही थी जो सदन के रिकॉर्ड में है और आज वही परिस्थिति आ गई। Last year, when this Government had announced Rs. 1080 per quintal price for wheat, a sizeable section of the farming community, particularly in Uttar Pradesh, shifted from sugarcane to wheat. अन्न का उत्पादन घटा। आज देश में सबसे ज्यादा चीनी उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है लेकिन उत्तर प्रदेश में ही गन्ने की लागत सबसे कम हो गई। उत्तर प्रदेश में चीनी का उत्पादन कम हो गया। इसके साथ नंबर दो पर महाराष्ट्र है और यहां उस समय उत्पादन घटा। जब दो राज्यों में उत्पादन घटा तब देश में चीनी की उपलब्धता कम हो गई और इसकी कीमत आज हम लोगों को देनी पड़ रही है। यह समस्या यहां तक सीमित नहीं हुई बल्कि दुनिया में सबसे ज्यादा चीनी उत्पादन करने वाले तीन देश आस्ट्रेलिया, ब्राजील और थाईलैण्ड और चौथा देश साउथ अफ्रीका है, इनमें ब्राजील को छोड़कर बाकी देशों में चीनी का उत्पादन घट गया। ब्राजील में इस साल गन्ने की लागत ज्यादा हुई है क्योंकि पिछले कई दिनों से कन्टीनुअसली बारिश आ रही है जिससे हार्वेस्टिंग और ट्रांसपोर्ट का ऑपरेशन बंद हो गया है और वहां चीनी मिलें नहीं चल सकी और उत्पादन रुक गया है। इसके कारण दुनिया में चीनी की कीमत ऊपर गई, भारत में चीनी की कीमत ऊपर गई और आज भारत में देशवासियों को एक जबर्दस्त संकट का सामना करना पड़ रहा है।

महोदया, मैं एक बात सदन को कहना चाहता हूं कि जब दुनिया की मार्केट में हिन्दुस्तान उतरता है तो दुनिया की मार्केट की कीमत नीचे जाती है और जब दुनिया की मार्केट में हिन्दुस्तान कुछ खरीदने के लिए जाता है तब दुनिया की कीमत ऊपर जाती है क्योंकि हम खरीदते ही इतने बड़े पैमाने पर हैं और इसका असर दुनिया पर होता है। आज चीनी हो या पल्सिस हो, इन दोनों क्षेत्रों में भारत के कारण यह परिस्थिति बनी है। इसका कुछ न कुछ रास्ता निकालने की आवश्यकता है। हमने इसके लिए पहला कदम उठाया कि 81 रुपए प्रति क्विंटल, मिनिमम सपोर्ट प्राइस में सुधार किया और 109 रुपए किया। इस तरह से इतनी वृद्धि इसमें की गई। इसके साथ दूसरा कदम उठाया। This is the Statutory Minimum Price; it is not the final price. चीनी मिलों को इससे ज्यादा कीमत देनी है और दे सकते हैं, अगर देने की परिस्थिति हो तो उन्हें देनी चाहिए। इसका फायदा यह होगा कि गन्ने की लागत बढ़ेगी। मुझे विश्वास है कि बारिश ने एक अलग तरह की परिस्थिति पैदा की है वरना इस देश में गन्ने का ज्यादा हिस्सा हो सकता था। हमारे सामने बाहर के देशों से चीनी लाने की समस्या थी। मैं आपको सच बताऊं तो हम बाहर से चीनी लाने के पक्ष में नहीं थे। लेकिन जब यहां का उपभोक्ता संकट में आ गया और इस तरह की परिस्थिति पैदा हो गई तब भारत सरकार ने कांसियस डिजीजन ले लिया कि हम बाहर से रॉ चीनी लेंगे। कुछ सदस्यों ने सवाल उठाया कि आप फाइन शुगर क्यों नहीं लाते, रॉ शुगर क्यों लाते हैं? इसका उत्तर यह है कि रॉ शुगर सस्ती होती है। हम यहां रॉ शुगर लाएंगे, अपनी चीनी मिलों में प्रॉसेस करेंगे जिससे चीनी मिलों की कैपिसिटी का यूटिलाइजेशन हो जाएगा, मजदूरों को रोजीरोटी मिलेगी और फिर उस चीनी को हम मार्केट में दे सकते हैं। हम तैयार चीनी लाएंगे तो डाइरेक्ट उपभोक्ता को दे सकते हैं लेकिन हम बाकी लोगों की मदद नहीं कर सकते हैं। हमने कांसियस डिजीजन लिया और इसके

सब टैक्सिस खत्म किए और चाहे जितनी रॉ शुगर लाएं, इसकी ऑलरेडी इजाजत दे दी है। About 29 lakh tonne raw sugar has reached in this country and the process will start from next month when actually the mills will start crushing. जब तक मिल शुरू नहीं होती तब तक यह प्रॉसेस होगा। जिन लोगों को चीनी मिली है उनके ऊपर एक बंधन लगाया है कि इम्पोर्ट करने के बाद तीन महीने के अंदर माल मार्केट में बेचना ही पड़ेगा, अवेलेबल करना ही पड़ेगा, अगर नहीं बेचा, स्टॉक किया तो यह जब्त हो जाएगा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन दुकान को दे दिया जाएगा। हमने इसके साथ इस तरह का कदम उठाया है। हमें उम्मीद है कि इसका कुछ न कुछ फायदा होगा और चीनी आने के लिए तैयार होगी।

पिछले कई सालों से हमारे देश में ऑयलसीड्स का उत्पादन कुछ क्षेत्रों में बढ़ा है। खास तौर पर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में विदर्भ का कुछ हिस्सा, कर्नाटक का कुछ हिस्सा और अन्य राज्यों के कुछ हिस्सों में सोयाबीन की फसल दिन-ब-दिन बढ़ रही है। सोयाबीन बढ़ रहा है, कुछ एरियाज में मस्टर्ड बढ़ता था, कुछ क्षेत्रों में कपास का तेल बढ़ता था और ग्राउंड नट तथा अदर्स फसलें भी ठीक तरह से होती थीं। लेकिन फिर भी डिमांड और सप्लाई में गैप थी और पिछले दस सालों से भारत ने, उसमें चाहे एनडीए सरकार हो या आज की हुकूमत हो, उन्होंने एडिबल ऑयल इम्पोर्ट करने की नीति स्वीकार की और आज इंडोनेशिया, मलेशिया और कुछ अन्य देशों से हम सोया ऑयल और पाम ऑयल बड़े पैमाने पर इम्पोर्ट करते हैं और डिमांड और सप्लाई के गैप को पूरा करने की कोशिश करते हैं।

महोदय, एक अच्छी बात है, पिछले एक महीने से दुनिया में, इंटरनेशनल मार्केट में ऑयलसीड और रिफाइंड ऑयल की कीमतें नीचे जा रही हैं।...(व्यवधान)

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद पूर्व): इससे देश में हर चीज का भाव बढ़ा है।

श्री शरद पवार : नहीं, तेल के भाव में फर्क पड़ा है।

श्री हरिन पाठक : एक-एक चीज का भाव बढ़ा है।

श्री शरद पवार : इसका असर देश के तेलों के भाव पर भी होने लगा है। चार दिन पहले मुझे एक डेलिगेशन मिला, जो इस देश में पैदावारी करने वाले लोग हैं और दूसरा केरल के हमारे कुछ साथियों का डेलिगेशन मुझे मिला। उन्होंने कहा कि आप विदेश से जो इयूटी फ्री ऑयल लाते हैं, उस पर आप कुछ न कुछ बंधन डालिये। यहां केरल के सदस्य होंगे। I hope, some hon. Members from Kerala are now present here. There was a demand from the farmers from Kerala that we should not allow easily the import of these oils, and particularly the import of these oils should be stopped in Kerala. That was the demand from the hon. Members from Kerala because it was affecting the interests of the domestic farmers of Kerala. ...(Interruptions)

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Sir, it is seriously affecting the coconut farmers in Kerala. ...(Interruptions)

SHRI SHARAD PAWAR: In fact, I am saying the same thing; what you are saying is correct. आज बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, इसका असर यहां के डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स पर हो रहा है। जो शिकायत अभी हमने केरल के सदस्यों के माध्यम से सुनी, ऐसी स्थिति आज अपने देश के कई एरियाज में पैदा होने लगी है। क्योंकि ऑयल सीड और रिफाइंड ऑयल बाहर से लाने के बाद यहां की कीमतें कम होने लगीं, इसका असर यहां के उत्पादन पर हो रहा है और इसलिए हमें इसका बैलेंस रखने की आवश्यकता है। हम उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना चाहते हैं। साइमल्टेनियसली डोमेस्टिक प्रोडक्शन खत्म नहीं होगा और यहां का किसान नाउम्मीद नहीं होगा, इस पर भी हम लोगों को ध्यान देना है। ...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): आप बताइये, कम कहां हो रहा है? यह बढ़ रहा है।...(व्यवधान)

श्री हरिन पाठक : आप बताइये कौन से देश में भाव बढ़ा है। Please name these countries. ...(Interruptions)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मंत्री जी के जवाब के बाद सवाल पूछेंगे तो अच्छा होगा, यदि बीच-बीच में पूछेंगे तो आपको जवाब नहीं मिलेगा।

â€¦(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इसलिए मंत्री जी को जवाब खत्म करने दीजिए।

श्री हरिन पाठक : आप बतायें कि इसका समाधान क्या है? महंगाई कम नहीं हुई है। साढ़े छः सालों से महंगाई बढ़ रही है, यह कम कब होगी।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये।

श्री हरिन पाठक : आम आदमी को इन सब बातों से क्या मतलब है।

SHRI SHARAD PAWAR: Why do you not listen? Please have some patience. ...(Interruptions)

Currently, in the international market, the price of the edible oil, as on 30th of July, 2009, is lower as compared to the same

date last year. Palm oil price declined by 37.76 per cent per tonne, FOB; the price of soyabean has declined by 43.6 per cent. ...(*Interruptions*)

श्री बसुदेव आचार्य : यह बाहर हो रहा है, लेकिन यहां नहीं हो रहा है।

श्री शरद पवार : मैं बताता हूँ...(*व्यवधान*)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बताने दीजिए। आप बैठ जाइये।

14.44 hrs. (*Madam Speaker in the Chair*)

श्री शरद पवार : आप यह तो मानते हैं कि बाहर हो रहा है...(*व्यवधान*) In the domestic market also, the wholesale price of the edible oil has declined in the same period; soyabean oil by 31.58 per cent; sun flower oil by 33.33 per cent; and palm oil by 30.77 per cent...(*Interruptions*)

SHRI BASU DEB ACHARIA : Are you talking about the wholesale price or the consumer price?â€ (*Interruptions*)

SHRI SHARAD PAWAR: If the wholesale price has come down, there are some repercussions on consumer price too.

SHRI BASU DEB ACHARIA : There are no repercussions...(*Interruptions*)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर): आप कंज्यूमर प्राइस के बारे में बता रहे हैं या होल सेल प्राइस के बारे में बता रहे हैं?

श्री शरद पवार : मैं दोनों के बारे में बता रहा हूँ। कुछ न कुछ असर इसके ऊपर भी हो रहा है।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : मैं कंज्यूमर प्राइस के बारे में जानना चाहता हूँ।...(*व्यवधान*)

SHRI SHARAD PAWAR: I would just like to give information...(*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये। आप ध्यान से सुनिये।

SHRI SHARAD PAWAR: I am just reading the statement. This is dated 6th August, retail price of the selected essential commodities in Delhi. You are referring about oil. On 6th August, 2008, the groundnut oil price in the city of Delhi was Rs. 121 per kilo; and today, it is Rs. 107 per kilo. About mustard oil, it was Rs. 85 per kilo on 6th August, 2008 and today, it is Rs. 65 per kilo. About vanaspati oil, it was Rs. 73 per kilo and today, it is Rs. 55 per kilo...(*Interruptions*) These are the official figures of Delhi...(*Interruptions*) If you are not willing to understand, what can I do?...(*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदय : आप लोग बैठ जाइये।

श्री लालू प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे माननीय सदस्यों के मन में यह जिज्ञासा है कि मंत्री महोदय के जवाब के बाद सब को मौका मिलना चाहिये। जो जानना चाहें, माननीय मंत्री जी बाद में उसका जवाब दे दें। अगर आप इस बात का इन्तजाम कर दें तो हल्ला-गुल्ला रुका रहेगा।

संसदीय कार्य मंत्री और जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): मंत्री जी के जवाब से स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। जितना समय इस विषय पर चाहिये था, उससे ज्यादा समय दिया जा चुका है।

MADAM SPEAKER: Hon. Minister, please continue.

SHRI SHARAD PAWAR: So, these are the important items. मैंने यह बात शुरु में साफ तौर पर कही है कि मैं ऐसा बिलकुल कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ कि देश में असेंशियल कौमोडिटीज की कीमतें ठीक तरह से नीच आ रही हैं जिससे आम जनता संतुष्ट हो जायेगी, मैंने ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया है। लेकिन यह बात मैंने जरूर कही है कि चीनी की कीमतें आज ऐसी परिस्थिति में पहुंची है कि हर सैक्शन प्रभावित है। चीनी के रेट्स नीचे लाने के लिये कुछ न कुछ कोशिश करनी पड़ेगी। इसके लिये इम्पोर्ट का रास्ता स्वीकारना पड़ेगा, सब्सिडी का रास्ता स्वीकारना पड़ेगा। साथ ही साथ लॉग टर्म प्लानिंग में इसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिये कोशिश करनी पड़ेगी। इस साल एक अलग सा माहौल पैदा हो गया कि वर्षा कम हुई है। इसलिये बारिश कम होने का असर इस पर हो गया। मैं ने इस बात को शुरु में स्वीकार किया है। मैं इस परिस्थिति को नजर-अंदाज नहीं करना चाहता हूँ। आम जनता को जो तकलीफ होती है, उस तकलीफ के बारे में इस सरकार को बिलकुल...(*व्यवधान*)

श्री लालू प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो सवाल किया, आपकी तरफ से उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ। बंसल जी ने कहा...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी का उत्तर पूरा हो जाने दीजिये।

श्री लालू प्रसाद : हम क्या करें, क्या चले जायें?

अध्यक्ष महोदया : नहीं, आप क्यों जायेंगे, आप पूरा उत्तर सुनिये।

श्री शरद पवार : आप कहां जायेंगे?

अध्यक्ष महोदया : आप उत्तर सुनिये, क्यों जायेंगे?

श्री शरद पवार : हमें छोड़कर कहां जायेंगे?

श्री लालू प्रसाद : हम यहीं हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव : जब आप इस पर कह रहे हैं कि उत्तर नहीं दिया जायेगा...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप पूरा उत्तर सुन लीजिये। इस पर चर्चा हो चुकी है। मंत्री महोदय उत्तर दे रहे हैं। मुलायम सिंह जी, आप शान्त हो जाइये।

श्री शरद पवार : अध्यक्ष महोदया, कुछ माननीय सदस्यों ने सब्जियों के रेट बढ़ने के बारे में कहा है। यह बात सच है कि पिछले कुछ समय से बारिश कम हो रही है। पानी की स्थिति देश में गम्भीर हो रही है जिसका असर सब्जियों पर पड़ रहा है। मगर सब्जियों के रेट्स में और पल्सेज के रेट्स में फर्क है क्योंकि सब्जियों की परिस्थिति देश में कभी परमानेंट नहीं रहती है।

यह मैंने कई बार देखा है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, वहां प्याज ज्यादा पैदा होता है। कभी प्याज की कीमत इतनी नीचे जाती है कि उसे मार्केट में ले जाने के लिए किसान का जो खर्चा लगता है, वह भी किसानों को नहीं मिलता है इसलिए उनकी आँखों में आंसू आ जाते हैं। कभी-कभी प्याज की कीमत इतनी ऊपर जाती है कि उपभोक्ता की आँखों में आंसू आ जाते हैं। यह बात हम लोगों ने कई बार देखी है। आज यह परिस्थिति पैदा हुई है। आज पूरे देश में सूखे की जो अवस्था है, उसका कुछ न कुछ असर उसके ऊपर हुआ है और हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। चाहे आलू हो या प्याज हो, इसका कुछ न कुछ असर हुआ है।...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : महोदया, दवाएं बहुत मंहगी हो गयी हैं, उसके बारे में मैंने सवाल पूछा था। दवाएं इतनी मंहगी हो गयी हैं कि गरीब आदमी इलाज नहीं करा सकता है। मंहगाई की वजह से, दवाओं के अभाव में सैंकड़ों लोग मर रहे हैं। दवाएं बहुत मंहगी हैं।...(व्यवधान) क्या कृषि मंत्री इस संबंध में बताएंगे।

अध्यक्ष महोदया : कृपया शांत हो जाइए। आप बैठ जाइए।

â€(व्यवधान)

श्री शरद पवार : महोदया, मुलायम सिंह जी ने सदन के सामने एक बात कही।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए। कृपया शांत हो जाइए।

â€(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: No, please take your seat.

â€(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : महोदया, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी, हम लोग सीनियर लीडर हैं।

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

श्री लालू प्रसाद : महोदया, हमारी बात सुन ली जाए। एक मिनट में हमारी बात सुन ली जाए। यहां मूल सवाल भूख का है। इस भूख में चावल गायब हो गया है। दाल के बारे में हम मानने को तैयार हैं कि शॉर्ट-फॉल है। गेहूं भी पैदा नहीं होने वाला है। आपके बफर स्टॉक में दो साल के लिए भोजन कराने का क्या प्रबंध है?...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कृपया बैठ जाइए। आप मंत्री जी को अपना उत्तर पूरा कर लेने दीजिए।

â€(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : आप पहले यह बताइए कि आपके बफर स्टॉक में केवल नमक और रोटी खाने के लिए कितना अनाज पड़ा हुआ

है?...(व्यवधान) आप उसके बाद चीनी पर आइए। अपलेट मार्केटियर्स है, होडर्स हैं, डिहोर्डिंग के लिए आप क्या कार्यक्रम बना रहे हैं?...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : लालू प्रसाद जी, कृपया आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

â€(व्यवधान)

श्री शरद पवार : यह बहुत अच्छा सवाल दोनों यादवों, चाहे लालू यादव जी हों, चाहे मुलायम सिंह जी हों, ने सदन के सामने रखा है। मुलायम सिंह जी ने किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए कहा है।...(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : मुलायम सिंह जी और मेरे बीच कंटीशन है।...(व्यवधान)

श्री शरद पवार : माफ कीजिए, आप दोनों और शरद जी भी एक हैं। उन्हें नजरअंदाज मत कीजिए।...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : आप तीनों यादवों से परेशान क्यों हैं?...(व्यवधान)

श्री शरद पवार : तीनों यादवों को मिलकर सदन को परेशान नहीं करना चाहिए, इसी में हमारा फायदा है। मैं माफी चाहता हूँ, यह मजाक की बात है। इसमें दो बड़े महत्वपूर्ण इश्यू रखे थे- regarding the Minimum Support Price, this Government has taken conscious decision to provide a better price to the farming community. मैं एक बात सदन के सामने कहना चाहता हूँ, इससे पहले भी मैंने कहा था कि हमारे यहां गेहूँ का उत्पादन कम हुआ था। इसी सदन में तीन साल पहले जब गेहूँ इम्पोर्ट करने की नौबत आ गयी थी, तब इसके ऊपर बड़ी नाराजगी पैदा हुई थी। यह बात साफ थी और इस पर ठीक तरह से कदम उठाने के लिए, गेहूँ की जो 600 रूपए कीमत थी, उसे 1000 रूपए करने का निश्चय डॉ. मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने किया था।

महोदया, दूसरे साल इसे 1,080 रूपए किया गया। आज लालू जी ने यहां सवाल उठाया। इसका यह फायदा हुआ कि आजादी के बाद आज तक इतना उत्पादन कभी नहीं हुआ था। आजादी के बाद आज तक गेहूँ का इतना प्रोक्योरमेंट कभी नहीं हुआ था। आज हमारे पास 252 लाख टन गेहूँ है। जैसा कि लालू जी ने कहा, अगले 13 महीने तक...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप लोग बैठ जाइए।

â€(व्यवधान)

श्री शरद पवार : आज हमें 252 लाख टन गेहूँ प्रोक्योर करने में कामयाबी मिली। अगले 13 महीने के लिए देश की जो जरूरत है, उतना गेहूँ सरकार के गोदाम में है।

जहाँ तक दूसरी बात लालू जी ने चावल के संबंध में कही, वह भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। चावल का आज तक इतना प्रोक्योरमेंट कभी नहीं हुआ था - 356 लाख टन के आस-पास चावल का प्रोक्योरमेंट हुआ है। अगले 13 महीने की देश की जो चावल की आवश्यकता है, वह देश के पास है।

एक समस्या सिर्फ हमारे सामने बिहार के कुछ क्षेत्रों से, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से आई है। इन राज्यों से आज जो चावल बाकी है जिसको उसना चावल भी बोलते हैं, पार-बॉर्डर राइस भी कहते हैं...(व्यवधान) इसकी एक स्थिति ऐसी है कि आज भी किसानों और मिलों के पास वह चावल है। उसको खरीदने की हमारी पूरी तैयारी है। मगर देश का कोई भी राज्य आज उसना चावल लेने के लिए तैयार नहीं है। जहाँ वह चावल पैदा होता है, कम से कम वहाँ तो हमने पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन के लिए दिया, इसको उन्हें स्वीकार करना चाहिए। चाहे आंध्र प्रदेश हो, बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो या उड़ीसा हो, इन राज्यों का आज जो माल पड़ा है, वह पूरा माल फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया खरीद करेगा और उन राज्यों को पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन को देना पड़ेगा। वह देने की हमारी तैयारी है, इनको स्वीकार करना पड़ेगा। नहीं तो यह माल खरीदने के बाद इसको देश में कोई स्वीकार नहीं करेगा तो उससे देशवासियों का नुकसान होगा, इतना ही मैं इस सदन के सामने रखना चाहता हूँ।

एक बात यहाँ कीमत के बारे में कही गई। जैसे मैंने कहा कि गेहूँ की कीमत, चावल और धान की कीमत अच्छी देने के लिए कोशिश की तो इसका असर हो गया। मगर इससे भी ज्यादा कीमत देने की माँग यहाँ की गई और खास तौर पर छत्तीसगढ़ के क्षेत्र से इस तरह की माँग आई है। मुझे कल छत्तीसगढ़ के मुख्य मंत्री जी का पत्र आया है। उन्होंने लिखा है और रिकमंड किया है कॉमन ग्रेड के लिए। Rs. 1,186 is the price for one quintal of paddy which has been proposed by the hon. Chief Minister of Chhattisgarh. In fact, one should go in detail. What will be the ultimate impact on price of rice? जब हम एक क्विंटल पैडी खरीदते हैं तो 65 किलो राइस मिलता है। If we pay Rs. 1,186 and add Rs. 148 of local taxes at the rate of 12.5 per cent, it will come to Rs. 1,334. Then, there will be *mandi* charges of Rs. 15. Rice recovery will be 67 per cent. Therefore, the cost of one quintal of rice will be Rs. 2,024. In addition, there will be cost of Rs. 50 towards gunny bags. So, the total price of one quintal is Rs. 2,074. आप समझो कि 2100 रुपये क्विंटल चावल की कीमत हो गई तो उपभोक्ता को किस कीमत पर हमें माल देना चाहिए? ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कृपया शांत रहिये।

श्री शरद पवार : 2100 रुपये आज हमने किसानों को दिये, वहाँ प्रोसेस करने के लिए लागत लगाई और 2100 रुपये का वह चावल सरकार के गोदाम में आकर पड़ा तो आम जनता को इसकी ज़बर्दस्त कीमत देनी पड़ेगी। मैं इस पक्ष में हूँ कि किसानों को अच्छी कीमत मिलनी चाहिए। सरकार ने जो कदम उठाए, यह इसलिए उठाए कि किसान को वह कीमत मिले जो कभी नहीं मिली थी। मगर कीमत देते समय हम उपभोक्ता को भी नज़रंदाज़ नहीं कर सकते। हमें इसमें बैलैन्स रखना होगा।

15.00 hrs.

बैलैन्स रखने के अप्रोच को इस सरकार ने आज तक स्वीकार किया है।...*(व्यवधान)*

There was an issue ...*(Interruptions)* which has been raised by some hon. Members, namely, that allocation of food grains for State Public Distribution System (PDS) has been reduced for BPL and AAY. I would like to make one position absolutely clear that not for a single State and not even one grain was reduced by this Government for BPL and AAY. ...*(Interruptions)*

SHRI P. KARUNAKARAN : As far as Kerala is concerned, the APL quota was reduced as compared to 2007. ...*(Interruptions)*

SHRI SHARAD PAWAR : I said that not a single grain has been reduced for BPL and AAY. Not only that, the price, which has been fixed in 2002, even today we are selling at the price of 2002 to the BPL category, and AAY ...*(Interruptions)* We have not enhanced the price. We have taken substantial burden, and that is the reason that the burden of the subsidy has gone up from Rs. 19,000 crore to Rs. 55,000 crore. Therefore, this type of burden this Government has taken just to protect the interest of vulnerable sections of the society. ...*(Interruptions)*

Secondly, there was a demand ...*(Interruptions)*

SHRI KHAGEN DAS (TRIPURA WEST): What about the APL category? ...*(Interruptions)*

SHRI SHARAD PAWAR : As regards Above Poverty Line (APL), we have taken a decision for supply of uniform minimum 10 kgs. Kerala was one of the States, which was always coming with some proposals, and I always try to accommodate it.

In fact, I saw the statement from one of the Ministers from Kerala day-before yesterday stating that : "We have approached the Government of India, the hon. Prime Minister, and the Agriculture Minister for some support and additional quota for the festival, but it was not accepted by the Government of India." I am sorry to say this. The hon. Chief Minister of Kerala and the hon. Civil Supplies Minister of Kerala Mr. Divakaran and their officials met me personally, and they gave a request that they want 50,000 tonnes additional quota of rice and 25,000 tonnes additional quota of wheat for the festival and that it has to be released as early as possible. I just told him then that we have assessed the stock position, and we said that : "Yes, we are ready to supply this. We can protect the interest of all the people from Kerala for the Onam festival."

The only question was about price. The price, whatever I am paying to the farmers, you will have to pay that money to us. Therefore, that price we are expecting from them. ...*(Interruptions)* We have made allocation to the State for 50,000 tonnes of rice and 25,000 tonnes of wheat. ...*(Interruptions)* Still, I have seen the statement from the Kerala leadership that the Government of India has not sanctioned a single grain to them. ...*(Interruptions)* I am sorry to say this. ...*(Interruptions)* This Government will never take this type of approach with any State Government irrespective of political party. ...*(Interruptions)* This is our total approach about it. ...*(Interruptions)*

Hon. Shri Basu Deb Acharia ...*(Interruptions)*

SHRI P. KARUNAKARAN : It is for the festival of Onam in Kerala. ...*(Interruptions)*

MADAM SPEAKER: Please take your seat. Let the hon. Minister reply.

...*(Interruptions)*

SHRI P. KARUNAKARAN : We would request the hon. Minister for this because this is for the Onam festival in Kerala. ...*(Interruptions)*

MADAM SPEAKER: Hon. Member, please take your seat. Kindly take your seat.

...*(Interruptions)*

SHRI SHARAD PAWAR : Please do not confuse things with it. ...*(Interruptions)*

SHRI P. KARUNAKARAN : What about the APL price, and not the BPL price? ...*(Interruptions)*

SHRI SHARAD PAWAR : Whatever price I am paying to the farmers ... (Interruptions) Additional quota from any State, they have to accept the price, which has been paid to the farmers. We do not want to take establishment charges and we do not want all the money that we are spending for interest, store charges, transport charges, etc. All the burden will be taken by the Government of India, but the money, which has been paid to the farmers has to be recovered from the respective States for additional quota. This type of decision is taken. ... (Interruptions)

As regards action on essential commodities, लालू जी ने होर्डिंग के बारे में कहा है। सभी राज्यों को भारत सरकार की तरफ से कहा गया है कि वह एसेंशियल क्मोडिटी एक्ट का आधार लेकर स्टॉक लिमिट, लाइसेंसिंग और स्टॉक डिक्लरेशन और होर्डिंग के खिलाफ कदम उठाने चाहिए।

देश के 18 राज्यों ने इसे स्वीकार किया और 13 राज्यों ने इस बारे में जो आर्डर इश्यु करने की आवश्यकता थी, वे इश्यु किए। इस साल राज्य सरकारों ने जो कदम उठाए हैं, वे बहुत कम हैं। आज तक इसमें जो होर्डर्स को डिटेन करने की आवश्यकता थी, ऐसे टोटल डिटेक्शन इस देश में चार राज्यों ने किए, उन्होंने 162 परसेंट आज तक बड़े व्यापारियों या कुछ लोगों को डिटेन किया, ऐसा रिकार्ड उन्होंने हमें दिया है। कल प्रधान मंत्री जी ने इस काम के लिए देश के सभी मुख्य सचिवों और बाकी लोगों की मीटिंग बुलाई है, सूखे की स्थिति का अंदाज लेंगे।... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : चार राज्य कौन से हैं?... (व्यवधान)

श्री शरद पवार: सूखे जैसी परिस्थिति के बारे में उत्तर प्रदेश नहीं है।... (व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : पहले भी प्रधान मंत्री जी ने सारे मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी थी, उस समय भी राज्यों से कोई सहयोग नहीं मिला था। आप सही बात नहीं बता रहे हैं, हम अगर एक लाख की दाल लेना चाहते हैं तो दाल मौजूद है और महंगाई आसमान पर है। ... (व्यवधान) ब्लैकमार्केटियर्स के खिलाफ होर्डिंग अभियान नहीं चलाएंगे, ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : लालू प्रसाद जी, मंत्री जी को उत्तर देने दीजिए।

â€¦ (व्यवधान)

SHRI SHARAD PAWAR: As a first step, tomorrow morning, at 10.30 a.m., a meeting of all the Chief Secretaries has been called to take a review of what exact action the State are taking to control the hoarders, the black-marketeers. We will find out what effective steps have been taken by them. There is also a proposal, I am not sure, that probably on the 17th of this month, a meeting of Chief Ministers may also be called just to discuss this. We will try to urge them that each State has to take very deterrent action against hoarders and black-marketeers. That action will be taken. The situation is very serious. The Government of India has taken this entire situation quite seriously. We have decided that whatever is available here, we will try to distribute it properly, and whatever shortfall is there, we will try to import it from anywhere in the world. Our efforts will be to see that there is no question of food shortage in this country, and common man should not be affected because of higher prices, which is beyond his control.

... (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Please sit down, you cannot be standing up all the time.

... (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Please sit down. We have had a debate. Please sit down.

... (Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA : He has not stated anything. We are walking out in protest.

15.07 hrs.

(At this stage, Shri Basu Deb Acharia and some other

hon. Members left the House.)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

â€¦ (व्यवधान)

श्रीमती सुआमा स्वराज (विदिशा): अध्यक्ष महोदया, लीडर ऑफ अपोजिशन बोलना चाहते हैं।... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी, आप बोलना चाहते हैं?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर): अध्यक्ष महोदया, देश में महंगाई के बारे में सदन में कई दिनों से कोशिश होती रही कि हम इस पर चर्चा करें। कल और आज जो चर्चा हुई है, जिसे कि हमारे सीपीएम के नेता ने आरम्भ किया, उसका इस समय जो जवाब दिया गया, मुझे नहीं लगता कि सदन को इस बात का संतोष हुआ, क्योंकि कुल मिला कर उत्पादन, प्रक्योरमेंट बढ़ा है, फिर महंगाई क्यों बढ़ी है? इस सरकार को कभी भूलना नहीं चाहिए, अभी-अभी आप जो चुनाव जीते, आपको अच्छा जनादेश मिला, उसमें प्रमुख रूप से आपने आम आदमी के प्रति न्याय करने का संकल्प किया था। अगर आम आदमी किसी बात से सबसे अधिक दुखी है, उसे तकलीफ है, गरीब की कैसी स्थिति होगी, जब दाल की कीमत बढ़ जाए। मंत्री जी ने सब्जियों की बात कही, लेकिन सबसे बड़ी तकलीफदेह बात यह है, ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, सदन का इस समय सत्रावसान होगा, हम राष्ट्रगान में जरूर सम्मिलित होंगे, लेकिन प्रोटेस्ट के तौर पर हम सदन का त्याग करना चाहते हैं।

15.09 hrs.

(Shri L.K. Advani and some other hon. Member then left the House)

â€ (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कृपया शांत रहिए। उन्हें बहिर्गमन करना है, शांतिपूर्वक करने दीजिए। आप शांत रहिए।

â€ (व्यवधान)
